Newspaper Clips
July 21, 2012

Tribune ND 21/07/2012 p-11

Entry to IITs just got tougher

In Punjab, Class XII students must score 70.8% to be eligible for entrance test

ADITI TANDON/TNS

NEW DELHI, JULY 20

From 2013, realising the IIT dream will get much tougher than most students thought.

In 15 states and UTs whose boards hold their own Class XII exams, IIT aspirants will have to score more than 60 per cent marks (IIT eligibility cut off which existed till 2012) for entry to the 15 coveted technical institutes.

A student in Andhra will, from 2013, have to score a minimum of around 87.20 per cent marks in Class XII to become eligible for IIT entrance while in Punjab, he will have to score 70.80 per cent, in Jammu and Kashmir 67 per cent and in Himachal 63.20 per cent.

For CBSE (national board) students, the qualifying percentage from the next year would have to be a minimum of 77.80 per cent.

The above stated percentages represent marks the last student in the top 20 percentile bracket of the respective state boards scored in Class XII in 2012. The Council of Boards of Secondary Education (COBSE) calculated the data to give IIT aspirants the idea of what Class XII percentage they should target from 2013 to ensure the eligibility for IIT entry.

On June 6, the IIT Joint Admission Board (JAB) had approved the new Class XII eligibility cut off formula replacing the old one where flat 60 per cent score in Class XII across boards was needed.

Under the new system, which gives more importance to school exams for IIT entrance, only those students will be eligible who figure in the top 20 percentile of all the exam writing students in a respective board in a given year.

The state/national boards in which students must score more than 60 pc in class XII for IIT eligibility are - Andhra: 87.2 per cent, Bihar: 64.6 per cent, CBSE: 77.8 per cent, Himachal: 63.2 per cent; J&K: 67 per cent, Karnataka: 67.50 per cent, Kerala: 76.5 per cent, Manipur: 64.6 per cent, Madhya Pradesh: 64 per cent, Maharashtra: 61.17 per cent, Punjab: 70.8 per cent, Rajasthan: 63.8 per cent, Tamil Nadu: 78.17 per cent, UP: 65 per cent and National Open School: 60.6 per cent.

Boards where less than 60 pc marks would do are West Bengal: 58 per cent, Uttarakhand: 55.20 per cent, Tripura: 50.80 per cent, Orissa: 56.33 per cent, Mizoram: 56.20 per cent, Nagaland: 49 per cent, Meghalaya: 49.40 per cent, Goa: 56.25 per cent, Chhattisgarh: 56.80 per cent and Assam: 54.20 per cent.

These percentages will end the confusion among students who did not know what top 20 percentile in their board means. IIT-JAB had asked COBSE to analyse Class XII marks attained in 2012 across state boards and publish the minimum percentage of marks scored by the last student in the top 20 percentile bracket of each board.

"These percentages are not likely to change much. Students should look at these targets for IIT eligibility," CBSE chairman Vineet Joshi said. He insisted the new system was more inclusive and took care of the fact that different boards awarded marks differently.

For instance, the last student in the top 20 percentile in Tamil Nadu board scored 78.17 per cent in Class XII this year as against just 49 pc in Assam and Meghalaya boards.

ADMISSION FORMULA

- Any student can take JEE Main exam, which will be a screening test for final admission to IITs
- 1.5 lakh toppers of Mains will be eligible to write JEE Advanced (to be held separately) for entry to IITs
- IIT-JAB will prepare the India merit list only for those among the 1.5 lakh toppers of Mains who also figure in the top 20 percentile of their respective board

Hari Bhumi ND 21/07/2012 P-3

आईआईटी में प्रवेश का सुनहरा मौका

2013 से लागू होगी समान एकल प्रवेश परीक्षा

हरिभूमि ब्यूरो .नई दिल्ली

■ छत्तीसगढ़ में प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम 56.80, मध्य प्रदेश में 64, उत्तर प्रदेश में 65, बिहार में 64.60 प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में अगले साल 2013 से लागू होने वाली समान एकल प्रवेश परीक्षा (सीईटी) से जुड़े टॉप ट्वेंटी पर्सेंटाइल फॉम्यूले के जरिए देश के तमाम बोड्र्स ने अपने न्यूनतम अंक प्रतिशत का ऐलान कर दिया है। इससे अब उन राज्यों के बच्चों को भी आईआईटी में प्रवेश का मौका मिलेगा जो कि पहले न्यूनतम अंक प्रतिशत में पिछड़ जाते थे।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक सीबीएसई समेत अन्य बोर्डों ने ट्वेंटी पर्सेंटाइल के हिसाब से अपने 12वीं बोर्ड के न्यूनतम अंकों का प्रतिशत जारी किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अध्यक्ष विनीत जोशी ने हरिभूमि से बातचीत में कहा कि आईआईटी में दाखिले के लिए पुराने नियमों के हिसाब से देश के तमाम बोड्र्स के लिए न्यूनतम 60 फीसंदी अंक निधारित किए गए थे। इससे कम अंक लाने वाले यानि गरीब और पिछड़े हुए राज्यों के बच्चों के लिए आईआईटी मात्र कोरा ख्वाब था। लेकिन अब सभी जगहों से बच्चों को समान मौका मिलेगा। नई प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ बोर्ड ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम 56.80 फीसदी अंकों का मानक तय किया है। मध्य-प्रदेश ने 64 फीसदी, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 65 फीसदी, बिहार बोर्ड ने 64.60 फीसदी, राजस्थान 63.80, पश्चिम बंगाल 58 फीसदी शामिल है। अंक प्रतिशत के मामले में आंध्र प्रदेश बोर्ड शीर्ष पर है। यहां 12वीं बोर्ड के न्यूनतम 87.20 फीसदी अंक पाने बच्चों ही परीक्षा में बैठ सकेंगे।

सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा के लिए न्यूनतम 77.80 फीसदी अंक मानक रखा है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों के लिए अंक प्रतिशत 60.60 फीसदी है। आंकड़ों के हिसाब से टॉप ट्वेंटी पर्सेंसाइल फॉम्युले से उत्तर पूर्व समेत उन बोड्र्स के बच्चों को आईआईटी में प्रवेश का मौका मिलेगा जिनका अंक प्रतिशत 55 फीसदी से नीचे रहता है। इनमें झारखंड 52.40 प्रतिशत, मेघालय ने 49.40 प्रतिशत, असम 54.20, नागालैंड 49, त्रिपुरा 50.80, उत्तराखंड 55,20 प्रतिशत शामिल है।

Amar Ujala ND 21-Jul-12 P13

साठ फीसदी से कम अंक पर भी आईआईटी में पा सकेंगे प्रवेश

अमर उजाला ब्यूरो

सीओबीएसई ने 26 बोर्डों का 20 पर्सेंटाइल आंकड़ा किया जारी

नई दिल्ली। आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए इंटरमीडिएट में 20 पर्सेंटाइल प्राप्तांक की शर्त जोड़े जाने से जहां सीबीएसई, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे बोर्ड के बच्चों की संख्या में कमी आएगी, वहीं उत्तराखंड सहित एक दर्जन राज्य बोर्डों से जुड़े बच्चों को ज्यादा संख्या में शामिल होने का मौका मिलेगा। सीओबीएसई द्वारा वर्ष 2012 के आधार पर 26 बोर्डों के 20 पर्सेंटाइल संबंधी जारी ताजा आंकड़ों से यह तथ्य उभरकर सामने आए हैं।

अभी तक इंटर की परीक्षा में 60 फीसदी से अधिक अंक हासिल करने वाले किसी भी बोर्ड के बच्चे आईआईटी प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते थे। हाल ही में आईआईटी कौंसिल द्वारा स्वीकृत नये परीक्षा पैटर्न में अब इंटरमीडिएट के लिए टॉप 20 पर्सेंटाइल का नियम तय किया गया है। सीबीओबीएसई द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार आंध्र प्रदेश बोर्ड में पढ़ रहे बच्चे को आईआईटी के लिए जहां 87 फीसदी या अधिक अंक लाना होगा, वहीं उत्तराखंड बोर्ड से 55 व छप्पन फीसदी अंक लाने वाला छात्र भी आईआईटी में प्रवेश पा सकेगा। सूची के अनुसार सीबीएसई में 78 फीसदी, हिमाचल में 63 फीसदी, जम्मू कश्मीर में 67 फीसदी, पंजाब में 71 फीसदी तथा उत्तर प्रदेश में 65 फीसदी से अधिक अंक पाने वाले छात्र 20 पर्सेंटाइल में शामिल होंगे। यह आंकड़ा विभिन्न बोर्ड के पिछले साल के परीक्षा परिणामों पर आधारित है।

अगले साल बोर्ड परीक्षाफल में ज्यादा फेरबदल नहीं होने पर 20 पर्सेंटाइल का आंकड़ा भी लगभग समान रहेगा। सीबीएसई चेयरमैन विनीत जोशी ने बताया कि यह आंकड़ा इसलिए जारी किया गया है कि जो बच्चे इस साल इंटर बोर्ड परीक्षा पास कर चुके हैं तथा 2013 में आईआईटी परीक्षा देना चाहते हैं वे अपना पर्सेंटाइल जान सकें। यही नहीं, 2012 में इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके बच्चे पर्सेंटाइल में आने के लिए 2013 में दुबारा परीक्षा दे सकते हैं।

Dainik Jagran ND 21/07/2012 P-11

इंटर में कड़ी मेहनत से ही पूरा होगा आइआइटी का सपना

राजकेश्वर सिंह, नई दिल्ली

अगर किसी छात्र का सपना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) में दाखिला लेने का है, तो वर्ष 2013 से अमल में आने वाले नए फार्मूले पर खरा उतरने के लिए इंटरमीडिएट में उसे और कड़ी मेहनत करनी होगी। आइआइटी के जेईई-एडवांस की मेरिट के साथ ही बोर्ड परीक्षा के टॉप 20 परसेंटाइल. छात्रों में शुमार होने की अनिवार्यता ज्यादातर राज्यों पर भारी पड़ सकती है। वैसे तो नए फार्मूले पर अगले साल से अमल होना है, लेकिन विभिन्न राज्यों के स्कूल शिक्षा बोर्ड के इस साल के नतीजों के आधार पर संभावित तस्बीर सामने है। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (कोब्से) ने 26 राज्यों की बोर्ड परीक्षा में पास हुए कुल छात्रों और उनमें टॉप 20 परसेंटाइल की श्रेणी में आने वाले छात्रों का आकलन किया है। इसके मुताबिक आइआइटी में दाखिले के लिए छात्रों को अब और मेहनत करनी होगी।

बढ़ती मुश्किलें

- नए फार्मूले के अमल से छात्रों के लिए बढ़ेगी कड़ी पढ़ाई की चुनौती
- 60-87 प्रतिशत अंक वाले छात्र भी टॉप 20 परसेंटाइल में सबसे नीचे

इस साल आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में पास हुए छात्रों में 87.20 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र टॉप 20 परसेंटाइल में सबसे नीचे रहे हैं। बिहार राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड में 64.60 प्रतिशत अंक और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65 प्रतिशत अंक, तमिलनाडु में 78.17 प्रतिशत, पंजाब में 70.80 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र भी टॉप 20 परसेंटाइल की श्रेणी में सबसे नीचे हैं। इसी तरह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) में 77.80 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र टॉप 20 परसेंटाइल में सबसे नीचे है। आइआइटी में दाखिले के लिए जेईई-एडवांस की मेरिट में आने के साथ ही टॉप 20 परसेंटाइल में भी आना जरूरी है। इस साल तक आइआइटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) में बैठने के लिए इंटरमीडिएट में 60 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होता था। इसके बाद आइआइटी-जेईई के अंकों के आधार पर दाखिले की मेरिट लिस्ट बनती रही है। कोब्से ने जिन राज्य स्कूल बोर्ड के इस साल के नतीजों का आंकलन किया है, उनमें 15 राज्य ऐसे है, जिनमें 87 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र भी टॉप 20 परसेंटाइल छात्रों की श्रेणी में सबसे नीचे है।

Hindu ND 21/07/2012 P-3

DU's meta university, college facing opposition

Staff Reporter

NEW DELHI: Trouble is brewing over Delhi University's ambitious plans to set up a meta university and a meta college, both of which are pending approval from the Executive and Academic Councils, which are due to meet over the weekend.

While members of the Delhi University Teachers' Association have been vociferously opposed to the ideas from the beginning, the calling of an emergency meeting of both Councils to approve the same, have riled them some more. "All members elected from the DUTA to the Executive and Academic Councils have been directed to vehemently oppose both resolutions from being passed," said DUTA member Abha Dev Habib, adding that the DUTA had also taken the decision to approach all their colleagues in both the Councils and ask them to desist from giving their approval. "We had a meeting running into several hours on Friday night," she added.

Some teacher organisations like the Democratic Teachers' Front has taken their disapproval further by bringing out detailed analysis of why the concept of a meta university and college would be disastrous, while alleging that the requisitioning of an emergency meeting smacked of foul play. "Two days before the university is to re-open, scheduling the emergent meetings to introduce provisions for credit transfer between Delhi University and other institutions and to introduce two new courses, Master of Mathematical Education and B. Tech in Humanities as models for meta university and meta college courses smacks off motives other than academic," said DTF president Shaswati Mazumdar.

The organisation in a statement urged members of the Academic Council to act responsibly, at least this time. "It is unfortunate that on many occasions in the recent past the AC has failed to live up to the role assigned to it as the academic body of the university and has simply nodded to the most ill-considered projects," said the statement.